(d) The total investment required to set up one such laboratory in the district was estimated at Rs. 1,86,500 as non-recurring towards cost of equipments and instruments and Rs. 1,62,000 per annum as recurring cost for technical staff, chemicals and consumables etc.

(e) The target is to set up one laboratory in each district by 31.3.1997. However, this will depend upon the response and specific proposals from the State Governments.

Investment by holding companies of MNCs

376. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of holding companies of multinationals who are seeking further investment in India as on 31st March, 1995; and

(b) the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) As on 31st March, 1995, there was only one proposal of a holding company of a multi National Company (MNC) seeking approval of Government for further investments in India. The details are as under:—

M/s. Pepsico Inc., USA was granted approval by Government of India on 22-02-94 for setting up a 100% holding company to invest in Indian subsidiary companies or in joint ventures or to directly engage in promotion of new export projects; Promotion of new joint ventures in export activities; Investments in Food Processing Industries; Investments in backward linkages with farmers by any of the companies of Pepsico Inc. in India; Investments in Beverage business — manufacturing, marketing and distribution; Investment in information technology and financial services; and Investment in technology upgradation.

Vide their letter, dated 30-12-94, the company requested Government for approval to enhance its equity from the approved equity of US $95.00 million for promoting new export projects, joint ventures in vegetable processing, value added branded Basmati rice and other activities. The company also proposes investments in agrobased snack foods and fruit juice based poroducts. The enhanced equity would also support investments in new beverages manufacturing units in Uttar Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Karnataka, Masharashtra and financial support to bottlers for investments in Rajasthan, Uttar Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. The company's request has been approved for enhancement of equity from US $95.00 million to US $180.00 million.

बिहार और गुजरात में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत औद्योगिक एकक

*377. **श्री जनार्दन यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित/निदेशित औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त आयोग द्वारा गुजरात के लिए लिए गए कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कितने सहकारी और वैयक्तिक एककों को सहायता प्रदान की गई?

उद्योग मंत्री (श्री के० करूणाकरन): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) अपने 82 सीधे सहायता प्राप्त संस्थान द्वारा बिहार राज्य में विभिन्न कार्यकलापों को संचालित कर रहा है। आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में इसकी 21 संस्थानों द्वारा हाथ में ली गई प्रमुख योजनाओं में फाइबर बनाना, सिल्क रिलिंग, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे उद्योग शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किये गये

कार्यों से उत्पादन तथा रोजगार में निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ा है:—

वर्ष	उत्पादन (रु० लाख में)	रोजगार (संख्या)
1992-93	8,789.46	81,299
1993-94	9,947.76	89,918
1994-95	10,857.94	94,084

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात और बिहार राज्य के०वी०आई० बोर्डों से धन प्राप्त सहकारी और वैयक्तिक एककों की संख्या इस प्रकार है:—

राज्य	वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
		सरकारी	वैयक्तिक	सरकारी	वैयक्तिक
गुजरात	1992-93	2	—	2	1534
	1993-94	2	—	6	1890
	1994-95	—	—	—	1434
बिहार	1992-93	—	—	—	—
	1993-94	7	—	—	78
	1994-95	—	—	—	44

आई०ए०एस० / आई०पी०एस० की परीक्षाओं में ओ०बी०सी० उम्मीदवार

*378. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष आई०ए०एस० / आई०पी० एस० / आई०एफ०एस० की परीक्षाओं में पिछड़े और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के कई उम्मीदवारों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये उम्मीदवार किन-किन राज्यों से हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से इनकी संख्या कितनी-कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा, 1994 में (परिणाम 23.6.1995 को घोषित) 31 अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों ने, जिन्होंने सामान्य श्रेणी के संस्तुत अंतिम उम्मीदवार से ऊपर का रैंक प्राप्त किया है, बिना कोई छूट / रियायत का लाभ उठाए सफलता प्राप्त की है। इन 31 उम्मीदवारों में से 8 उत्तर प्रदेश, 11 बिहार, 3 आन्ध्र प्रदेश, 6 तमिलनाडु, 2 कर्नाटक तथा एक महाराष्ट्र से है।

Ischemic Heart Diseases

*379. SHRI O.P. KOHLI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether 10% people in Delhi suffer from various levels of ischemic heart disease as per the survey conducted jointly by the AIIMS and Sita Ram Bharatia Institute;

(b) if so, whether Indians are more prone to this heart disease than people in Malaysia, China, Britain or the USA; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken for prevention as well as treatment of ischemic heart disease, particularly in Delhi?